DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
NAME OF NEWSPAPER

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली। मंगलवार • 29 अक्टूबर • 2024

लैंड पूलिंगः दो माह से धरने पर बैठे हैं किसान

नई दिल्ली। मास्टर प्लान 2041, लैंड पूलिंग और डीडीए पॉलिसी किसान हितैषी संशोधन के साथ लागू करने के लिए दौलतपुर और कंझावला में किसान दो माह से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसान गरीब मजदूर, युवा बेरोजगार नागरिक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की रुकी हुई शहरी विकास नीतियों को तेजी से लागू किया जाए। दिल्ली देहात विकास मंच ने कहा कि दिल्ली के विकास की मांगें नहीं मानी गईं तो धरने को बड़ा जनआंदोलन में बदलने का निर्णय लिया है। दौलतपुर और कंझावला में धरने पर बैठे बदन, अशोक यादव, करतार सिंह डबास, करण सिंह व आशीष डबास ने कहा कि हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, स्थिति गंभीर है। 50 लाख से अधिक लोगों के पास उचित सीवर कनेक्शन नहीं है। दिल्ली की बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत है, जो 10 लाख लोगों को प्रभावित करती है। विकास के वादों के बावजूद किसान, ग्रामीण और व्यापारी अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मास्टर प्लान दिल्ली 2041 और लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करते हैं तो उम्मीद है कि 17 लाख नए घर बनाए जाएंगे।

पंजाब केसरी DELHI
29 अक्तूबर, 2024 ▸ मंगलवार

बिधूड़ी ने जताया एलजी वीके सक्सेना का आभार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना से मुलाकात कर दिल्ली की जनता को दिए गए दिवाली के तोहफों पर उन्हें धन्यवाद दिया। कहा कि इन सौगातों से जनता को काफी राहत मिली है। बिधूड़ी ने मुख्य रूप से डीडीए से जुड़े अनेक मुद्दों पर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाल ही में उपराज्यपाल के आदेश से किसानों को म्युटेशन की सुविधा दी है। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों और गावो में बिजली के कनेक्शन के लिए डीडीए से ली जाने वाली एनओसी की शर्त हटाई गई है। भाजपा के सभी सांसदों ने उपराज्यपाल से मिलकर इसका अनुरोध किया था। इसके अलावा बिधूड़ी ने दिल्ली के गांवों के विकास के लिए उपराज्यपाल सक्सेना द्वारा 1000 करोड़ रुपए जारी करने पर भी उनका धन्यवाद किया गया। इससे गांवों में रुके हुए विकास कार्य शुरू हो सके हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--------- दैनिक भास्कर मंगलवार 29 अक्टूबर, 2024 -------DATED------------------------

ग्राउंड रिपोर्ट • आनंद विहार में दर्जनों जगहों पर फेंकी जा रही निर्माण सामग्री

प्रदूषण के लिए सरकारी एजेंसियां ही जिम्मेदार, सड़कों पर फेंक रहीं कचरा

गाजीपुर सब्जी मार्केट

गाजीपुर सब्जी मार्केट के सामने खुले बंजर मैदान में धूल और प्लास्टिक वेस्ट से फैल रहा प्रदूषण।

आईएसबीटी आनंद विहार रोड

गाजीपुर आनंद विहार आईएसबीटी अंडरपास और फ्लाईओवर बीच रोड पर डाला गया मलबा।

आनंद विहार बस अड्डा

आनंद विहार बस अड्डे के सामने डीडीए लैंड पर पीडब्ल्यूडी, एमसीडी के द्वारा डाला गया मलबा।

शेखर घोष | नई दिल्ली

दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालत लगातार खराब होते जा रहे हैं। हालांकि, सोमवार को एक दिन पहले की तुलना में प्रदूषण के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में मामूली गिरावट नजर आई। रविवार के 356 की तुलना में सोमवार को औसत एक्यूआई 328 दर्ज किया गया, लेकिन अब भी ये बेहद खराब श्रेणी में है और बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर मरीजों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण आईटीओ और आनंद विहार में दर्ज किया जा रहा है, जहां रविवार को एक्यूआई 405 दर्ज किया गया था। ऐसे में प्रदूषण के हॉट स्पॉट आनंद विहार में दैनिक भास्कर संवाददाता ने ग्रांउड रिपोर्ट में पाया कि यहां पर भारी प्रदूषण के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जैसी सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं।

भास्कर की पड़ताल में पता चला है कि दिल्ली सरकार का प्रदूषण रोकने का अभियान केवल कागजों पर ही चल रहा है। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी जैसी दिल्ली सरकार की कई एजेंसियां निर्माण सामग्री (सीएंडडी) खुले में सड़कों पर फेंक रही हैं। सरकारी एजेंसियां सड़कों के किनारों फेंके गए भवन निर्माण कचरा, मिट्टी के ढेर, धूल प्रदूषण बढ़ा रही हैं। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने मौके से निर्माण सामग्री को उठाकर लैंड फिल साइटों के बजाय आनंद विहार में दर्जनों जगहों पर फेंक दिया है। आनंद विहार बस अड्डे के सामने तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन को किराए पर लेकर पीडब्ल्यूडी और एमसीडी वहां सड़कों पर निर्माण स्थलों और नालों से मलबा उठाकर खुले में फेंक रहे हैं। इस वजह से वहां बड़े पैमाने पर धूल उड़ कर पीएम 2 और बस अड्डों से पीएम 10 हवा में घुलकर प्रदूषण फैला रही है।

खुली जगहों पर नहीं किया जा रहा पानी का छिड़काव

ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान भास्कर संवाददाता ने पाया कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए खुली जगहों पर पानी का कोई छिड़काव नहीं किया जा रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि यहां पर न तो कोई वेस्टेज डंप उठाने के लिए आता है और न यहां पर सफाई की जा रही है। हवा चलने के दौरान यहां धूल और प्लास्टिक के कण उड़ते रहते हैं, जबकि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा है कि दिल्ली सरकार ने 14 हॉट स्पॉट की पहचान की है। इन हॉट स्पॉट पर पानी के छिड़काव के अलावा प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई गई टीम प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान करती है और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करती है।

सुबह सैर को निकले लोग शिकायत होने पर लौटे घर

दिल्ली में सोमवार की सुबह सैर के लिए निकले लोगों को आंखों में जलन और उल्टी की शिकायत होने पर वे घरों में लौट गए। सुबह 7 बजे दिल्ली के 35 इलाकों में से 7 खराब श्रेणी में रहे, जबकि बाकी सभी 28 इलाके में प्रदूषण की हालत अभी भी बेहद खराब बनी हुई है। सबसे अधिक 376 एक्यूआई बबाना में दर्ज किया गया। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि खुले मैदानों, फ्लाईओवरों के नीचे अगर सरकार तात्कालिक उपायों के तहत इन जगहों पर लगातार दो घंटे पानी का छिड़काव अच्छा से कर इन मिट्टी और सड़क किनारे फेंके गए वेस्ट को गीला रखे, या प्लास्टिक से ढक दें तो भी प्रदूषण से बचा जा सकता है।

कई बार अधिकारियों से कहा, पर कोई उपाय नहीं किया

पड़ताल में पता चला है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के उपायों को जमीन पर इम्प्लीमेंट करने में बुरी तरह से असफल रही है। आनंद विहार बस टर्मिनल के सामने डीडीए की जमीन पर तैनात सुरक्षा गार्ड ब्रजेश कुमार ने बताया कि उनके रोकने के बाद भी पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, बाढ़ व नियंत्रण विभाग जैसे विभागों के कर्मचारी ट्रकों, टिप्परों से निर्माण सामग्री और नालों की गाद यहां पर फेंक रहे हैं। उन्होंने विभाग को बताया कि इससे प्रदूषण तेजी से फैलता है, इसके बावजूद विभाग के लोग जबरन मलवा फेंक रहे हैं। उन्होंने इसकी सूचना पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी दी, पर अधिकारियों ने कोई उपाय नहीं किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, OCTOBER 29, 2024 -----------DATED-----------------------

Bidhuri meets LG, discusses DDA matters

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Bharatiya Janata Party MP from South Delhi, Ramvir Singh Bidhuri, met lieutenant governor VK Saxena on Monday to discuss issues related to Delhi Development Authority (DDA), where the LG also serves as chairperson.

Following the meeting, Bidhuri shared that, under the LG's order, the facility for mutation was extended to farmers. "This has benefited thousands of people in the villages because mutation was earlier not allowed, and the names of the heirs of the farmers who died were not being recorded in the revenue records," he said.

Bidhuri also noted the removal of the requirement for obtaining a No Objection Certificate (NOC) from DDA for electricity connections in unauthorised colonies and villages in Delhi, a change that all BJP MPs had previously requested from the LG. "After this condition was removed, thousands of people have received electricity connections so far," he added.

Additionally, Rs 1,000 crore was allocated for the development of Delhi's villages, which has facilitated the resumption of stalled development work in these areas, according to Bidhuri.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS: पंजाब केसरी DELHI — 29 अक्तूबर, 2024 ▸ मंगलवार

दिल्ली विकास प्राधिकरण

निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय–सीमा में बढ़ोतरी

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि डीडीए द्वारा लीज होल्ड आधार पर आबंटित आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और सांस्थानिक प्लॉटों का निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि की समय–सीमा को 31.12.2025 तक बढ़ाया जाएगा। समय–सीमा में यह विस्तार अंतिम होगा, जो निर्माण कार्य पूरा करने हेतु समय–सीमा में विस्तार प्राप्त करने वाले आबंटितियों के लिए अंतिम अवसर होगा। यदि लीजहोल्ड आधार पर भूमि प्राप्त करने वाले इन आबंटितियों द्वारा निर्माण कार्य पूरा करने हेतु दिनांक 31.12.2025 तक समय–सीमा में विस्तार के इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो उनकी लीज को समाप्त कर दिया जाएगा तथा आबंटित भूमि का कब्जा डीडीए द्वारा तत्काल ले लिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।
@ddaofficial @official_dda @official_dda_ पर हमें फॉलो करें।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2024

दिल्ली विकास प्राधिकरण

निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय–सीमा में बढ़ोतरी

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि डीडीए द्वारा लीज होल्ड आधार पर आबंटित आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और सांस्थानिक प्लॉटों का निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि की समय–सीमा को 31.12.2025 तक बढ़ाया जाएगा। समय–सीमा में यह विस्तार अंतिम होगा, जो निर्माण कार्य पूरा करने हेतु समय–सीमा में विस्तार प्राप्त करने वाले आबंटितियों के लिए अंतिम अवसर होगा। यदि लीजहोल्ड आधार पर भूमि प्राप्त करने वाले इन आबंटितियों द्वारा निर्माण कार्य पूरा करने हेतु दिनांक 31.12.2025 तक समय–सीमा में विस्तार के इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो उनकी लीज को समाप्त कर दिया जाएगा तथा आबंटित भूमि का कब्जा डीडीए द्वारा तत्काल ले लिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।
@ddaofficial @official_dda @official_dda_ पर हमें फॉलो करें।

Hindustan Times — NEW DELHI TUESDAY OCTOBER 29, 2024

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Extension of Time by DDA for Completing Construction

Delhi Development Authority has taken a decision that the maximum period of Extension of Time for completing construction on the Residential, Commercial, Industrial and Institutional Plots allotted by DDA on lease hold basis, shall be extended till 31.12.2025. This is the last and final extension affording last opportunity to such allottees for availing Extension of Time for completing construction. In case these allottees of land on leasehold basis fail to avail this last and final opportunity of Extension of Time for completing construction within the extended time period up to 31.12.2025, their leases shall be determined forthwith and the possession of allotted land shall be taken-over by DDA forthwith.

For more details visit DDA's website www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800110332
Follow us on @ddaofficial @official_dda @official_dda_